

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 19 August 2026

जम्मू-कश्मीर में 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो सकती है जनगणना, सरकार ने दी बड़ी अपडेट ।

Publisher

Published on 04 Jun 2025



लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी इसी तारीख से होगी शुरुआत, पहली बार जातिगत और आर्थिक आंकड़ों की डिजिटल गणना ।

जनगणना 2026: जम्मू-कश्मीर से होगी शुरुआत, जाति और आर्थिक आधार की भी होगी गणना

भारत में वर्षों से लंबित जनगणना की प्रक्रिया अब गति पकड़ती दिख रही है । सूत्रों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में 1 अक्टूबर 2026 से जनगणना शुरू हो सकती है । यह जनगणना न केवल जनसंख्या की गिनती तक सीमित होगी, बल्कि इसमें जातिगत और आर्थिक स्थिति की भी विस्तार से जानकारी जुटाई जाएगी ।

यह पहला मौका होगा जब जातिगत जनगणना डिजिटल माध्यम से की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और समय की बचत होगी । सरकार का लक्ष्य है कि पूरी प्रक्रिया 3 वर्षों में पूरी की जाए, जबकि पहले इसमें करीब 5 साल तक का समय लगता था ।

डिजिटल होगी जातिगत जनगणना

सूत्रों ने बताया कि इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, जिसमें घर की प्रकृति (पक्का/कच्चा), वाहन की उपलब्धता, आय का स्रोत, जैसे सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को भी दर्ज किया जाएगा । इस प्रक्रिया में परिवार की जाति से जुड़ी जानकारी भी इकट्ठा की जाएगी ।

1 मार्च 2027 से होगा जनगणना का दूसरा चरण

हिमालयी राज्यों के बाद 1 मार्च 2027 से देश के अन्य हिस्सों में जनगणना की प्रक्रिया आरंभ होगी । यह समय यूपी जैसे बड़े राज्य

में विधानसभा चुनाव के आस-पास का भी है, जिससे यह प्रक्रिया **राजनीतिक दृष्टि** से भी महत्वपूर्ण बनती है।

केद्र सरकार का रुख : राजनीति से अलग, पारदर्शी सर्वे का लक्ष्य

30 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार की **कैबिनेट** ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मुख्य जनगणना में ही **जातिवार गणना** शामिल करने की घोषणा की थी। सरकार ने स्पष्ट किया कि अब तक कुछ राज्यों ने जातिवार सर्वेक्षण किए हैं, लेकिन वे **पारदर्शिता** और उद्देश्य की दृष्टि से भिन्न रहे हैं।

सरकार का कहना है कि: **“इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा सामाजिक ताने-बाने को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखने हेतु मुख्य जनगणना में ही जातिवार गणना कराने का निर्णय लिया गया है।”**

जातिगत जनगणना पर राजनीतिक प्रतिक्रिया

जातिगत जनगणना को लेकर **कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी** जैसी **विपक्षी पार्टियां** लगातार बीजेपी को घेरती रही हैं।

हालांकि जब **केद्र सरकार** ने इसे लागू करने का निर्णय लिया, तो विपक्षी दलों ने इसका श्रेय लेने की कोशिश की।

वर्ष 2010 में तत्कालीन **प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह** ने भी **जातिवार जनगणना** पर विचार के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया था, लेकिन तब कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका।

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.